



परिवहन का नया खाका, क्या घटेगी लागत?

एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी इस बात की स्वीकारोक्ति है कि देश के परिवहन बुनियादी ढांचे की प्रभावी योजना अलग-अलग विभागों में बांटकर नहीं बनाई जा सकती। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग और शहरी

परिवहन एक-दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। इसके बावजूद निवेश संबंधी फैसले अभी भी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के स्तर पर लिए जाते हैं और अक्सर व्यापक परिवहन नेटवर्क पर उनके प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता। आईटीएलए का उद्देश्य इसी कमी को दूर करना है। यह 10 वर्ष से अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा, परिवहन मंत्रालयों की क्षेत्रवार और वार्षिक योजनाओं का आकलन करेगा, 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय बुनियादी ढांचा

परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगा, उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और परियोजना पूरी होने के बाद प्रभाव का आकलन करेगा। साथ ही यह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ई-वे बिल, फास्टेग, वाहन और परिवहन से जुड़े अन्य आंकड़ों जैसे स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय परिवहन डेटा रिपॉजिटरी भी बनाएगा।

यह विचार सही है। परिवहन नीति का उद्देश्य अलग-अलग परिवहन साधनों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना नहीं बल्कि लोगों और सामान की आवाजाही में लगने वाली लागत और समय को न्यूनतम करना होना चाहिए। एक नया राजमार्ग उपयोगी हो सकता है लेकिन उसका आर्थिक लाभ इस बात पर निर्भर कर सकता है कि उससे रेल संपर्क, बंदरगाह या लॉजिस्टिक्स हब जुड़ा है या नहीं। इसलिए एकीकृत नियोजन से पूंजी का बेहतर आवंटन हो सकता है, दोहराव वाले निवेश को कम किया जा सकता है और लॉजिस्टिक्स की लागत घटाई जा सकती है। देश में समन्वय के लिए संस्थाएं तो अक्सर बनाई गई हैं लेकिन उन्हें समन्वय करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए। कई शहरों में प्रस्तावित एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) काफी हद तक सलाहकारी संस्थाएं बनकर रह गए हैं क्योंकि परिवहन बुनियादी ढांचे, संचालन और वित्त पर नियंत्रण रखने वाली एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती रही हैं। दिल्ली में यूएमटीए स्थापित करने के नए प्रयास इस बात की याद दिलाते हैं कि एक ही महानगरीय क्षेत्र के भीतर भी एकीकरण कितना कठिन है। खासकर जब जिम्मेदारियां और वित्तीय संसाधन अलग-अलग एजेंसियों में बंटे हों। यही सबक आईटीएलए पर भी लागू होता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक विशेष प्रयोजन इकाई के रूप में गठित किए जाने के कारण किसी परिवहन मंत्रालय के अधीन होने के बजाय आईटीएलए में विभिन्न परिवहन साधनों के बीच अधिक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता है।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति की 15वीं बैठक : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में अंतरराज्यीय जल सहयोग के नए आयाम स्थापित

नर्मदा जल के बेहतर उपयोग से जलाभावग्रस्त क्षेत्रों को मिलेगी राहत-मुख्यमंत्री शर्मा

सहमति, समन्वय, सहयोग और विश्वास से दशकों से लम्बित जल समझौतों ने लिया मूर्त रूप

पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार का लक्ष्य

अधिशेष नर्मदा जल भंडारण के लिए तैयार हो रही परियोजना रिपोर्ट

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net



नर्मदा नहर परियोजना जल दक्षता का अनूठा मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जल दक्षता का अनूठा मॉडल स्थापित किया है। जालौर और बाड़मेर जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों तक इस परियोजना में सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति को अविचार्य करने की पहल की गई है। इस सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी की छीजत नगण्य हुई है। साथ ही, 2.46 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में निर्धारित 40 प्रतिशत सिंचाई सघनता के लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा रहा है। किसानों की फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। यह पहल पूरे देश के लिए कुशल जल संरक्षण और उपयोग की उत्कृष्ट मिसाल है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन और जनजीवन की जीवनरेखा है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए जल की सुनिश्चित उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का सकारात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

अधिशेष जल के भंडारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। हमारा उद्देश्य मानसून के दौरान व्यर्थ बहने वाले अतिरिक्त पानी को संरक्षित कर प्रदेश के जलाभावग्रस्त क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय से अंतरराज्यीय जल सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता जैसे ऐतिहासिक समझौतों ने जलाभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद जगाई है। वहीं, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ने सहकारी संघवाद की भावना से नर्मदा परियोजना के अंतर्गत सराहनीय कदम उठाए हैं।

उपलब्ध अधिशेष जल के उपयोग के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

TRADITION Has Its OWN TREND

**₹3,499 की खरीदारी करें और
पाएं एक आकर्षक उपहार!***

*नियम व शर्तें लागू। ₹3,499/₹4,999/₹7,999 की खरीदारी पर ₹249/₹449/₹599, ₹799, ₹999 में उपहार पाएं।



Also available on **AJIORUSH**

Delivery starting 30 mins

VISA 10% OFF*

*T&C apply. Up to ₹500 discount. Minimum Shopping ₹3000. Once per card per month. Date: Valid till 31st December 2026. Valid on Tap to Pay with Visa Debit Card & Platinum Credit cards. Offer is applicable on both card tap and mobile tap transactions.

समन्वय दिनेश भारती ने काता में स्वरूप पदक तथा गुरुनिधान सिंह रत्नावत ने काता में स्वरूप पदक प्राप्त किया। खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि में कोच अशोक पारीक के समर्पित प्रशिक्षण, अनुशासन एवं निरंतर मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक आयोजित

बजट घोषणाओं एवं स्कीमेटिक योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारें

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज (सीओएस) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने मिशन कर्मयोगी, प्रक्रियाधीन भतियों, विभागीय स्कीमेटिक योजनाओं, बजट घोषणाओं की प्रगति, राजकाज पोर्टल पर फाइलों के निस्तारण, राजस्थान संपर्क पोर्टल तथा संभावित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रबंधन की विभागवार विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भर्तियों की समीक्षा एवं आगामी रोजगार मेले की तैयारी

मुख्य सचिव ने अर्धकालिक राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और 5 वर्षों में 4 लाख रोजगारियों को रोजगार के अवसरों के साथ काली विनियमिता जा जा रहा है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 रोजगार मेमोर्ला एव विभिन्न भर्ती प्रि याओं के माध्यम से 1 लाख 90 हजार 894 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा लोभमग 1 लाख 10 हजार 100 पदों पर भर्ती की कार्यवाही विभिन्न स्टॉप पर प्रि याधीन है, जिनमें से 45 हजार 645 पद पर प्रि याधीन हैं। आगामी समय में नियुक्तियां दी जानी संभावित



है। मुख्य सचिव ने आगामी रोजगार मेले में दी जाने वाली निष्कर्षियों से संबंधित सुचनाएं शीघ्र आउट करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रैर याधनी भर्तियों में तेजी लाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रभावी समन्वय स्थापित कराने की व्याख्यालान में लंबित प्रकरणों में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आगामी वर्ष के भर्ती परीक्षा के दौरान के लिए सभी विभागों को रक्त पदों की गणना कर शीघ्र अर्धनामिजवाने के निर्देश दिए।

बजट घोषणाओं एवं स्कीमेटिक योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन-

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने शेष लंबित मुद्दों पर घोषणाओं तथा जिन घोषणाओं की स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी हैं, उनके कार्य शीघ्र धरातल पर उतराने के निर्देश दिए। विभागीय स्क्रीमैंटिंग एजेंसियों से योजनाओं की समीक्षा के दौरान सूचीस्थ व्यय ने कहा कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर

माह के अंत तक स्क्रीमेटिक बजट के विल्ट्ड 1 लाख 1 हजार 969.52 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। यह गत वर्ष 2025-26 को इसी अवधि में हुए 87 हजार 695.12 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में 16.28 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने अधिकारियों को सूचित राशि के समनवयव उपयोग के लिए स्वयं के स्तर पर नियमित समीक्षा करने तथा केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से निरंतर समन्वय बनाकर योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए।

**नरेन्द्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में
संभाला जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार**

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

इससे पूर्व वे जिला सूचना एवं जनसं-
कार्यालय, जयपुर में तीन वर्ष से अधिक र-
तक सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद-
कार्यरत रहे। जिला स्तर पर कार्य करते-
उन्होंने सरकारी योजनाओं, नीतिगत नि-
र्देशन-व्यवस्थापक कार्यक्रमों और प्रशास-
न-विधियों से संबंधित सूचनाओं के संक-
लेखन तथा प्रचार-प्रसार का अनुभव-
किया। नरेन्द्र सिंह शेखावत की पदे-
विभागीय प्रतियां के तहत हुई है। जिला सू-
चना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जयपुर में तीन व-
र्ष अधिक की सेवाओं में, मुख्यमंत्री कार्याल-
य पिछले छह मास से एपीआरओ के रूप में-
करने तथा प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में-
अनुभव के साथ उन्होंने अब मुख्य-
कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में-
जिम्मेदारी संभाली है।

**चारू मीणा एपीआरओ से बनीं पीआरओ ,
जयपुर कलेक्ट्रेट में संभाला कार्यभार**

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के तहत चारू मीणा को सहायक जनसंपर्क अधिकारी (एपीआरओ) से जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के पद पर पदोन्नत किया गया है। उल्लेखनीय है कि चारू मीणा वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जयपुर में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। विभागीय आदेश की अनुपालना में उन्होंने उपनिदेशक हेमंत सिंह को जनसंपर्क अधिकारी के पद का कार्यभार प्रविष्टित प्रस्तुत कर जनसंपर्क अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। चारू मीणा की पदोन्नति पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक चुनौतियों के समाधान का सशक्त माध्यम-देवनानी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पक्षधर बने विश्व समुदाय

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी ने नई दिल्ली स्थित संसद में भाग लिया। देवानी ने कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान, विभिन्न देशों में संसदीय समन्वय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की मजबूती सदस्यता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, संसद एवं विधान संस्थाओं में सांथक बहस और पक्ष-विपक्ष की जिम्मेदारिता सहित विभिन्न विषयों पर ब्रिक्स सम्मेलन महत्वपूर्ण है। देवानी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की संसदीय बैठक का विशेष महत्व है। क्योंकि इन देशों में विश्व की आधी आबादी निवास करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, आतंकवाद और सह-अस्तित्व जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इन विषयों पर विभिन्न देशों की संसदों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है, ताकि सभी देश मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल सकें।

मानव जीवन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता

देवनांनी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जबकि विभिन्न देशों के बीच तनाव और क्षेत्रवाद जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तब मानव जीवन के स्तर को उँचा उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र की जननी एवं आत्मा है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी है कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों के साथ मिलकर प्रयास करे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण

देवनांनी ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी और निष्पक्ष प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विश्व के विशिष्ट संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में भारत का अग्रगण्य बनता है। उन्होंने कहा कि कई देश भारत की इस दायित्वों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिरता बढ़ी है। जब तक संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन भारत जैसे देशों को समुचित रूप से सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक उनकी प्रासंगिकता, कार्यप्रणाली और निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता में अपेक्षित सुधार नहीं आ सकेगा। देवनांनी ने विश्वास

देशों में से कई देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और विदेश नीति के सफल प्रयासों के कारण आज विश्व के अधिकांश बड़े और छोटे देश भारत के समर्थन में खड़े हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में सार्थक बहस और जनसमस्याओं पर चर्चा आवश्यक

अपने लेखनमात्र ने नगरपालिका, पंचायत, विधानसभाओं और लोकसभा तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार तथा नवगर्भ की संभावनाएं बताई। उन्होंने कहा कि भारत एक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां प्रत्येक पांच वर्ष में नगरपालिका, पंचायत, विधानसभाओं और लोकसभा में चुनाव होते हैं। पिछले पांच में अधिक का प्रतिशत भी बढ़ा है। पंचायतों में 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की सहभागिता देखने को मिलती रही है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बढ़ने के साथ ही लोगों की ओझाएं भी बढ़ी हैं। स्थानीय समस्याओं के समाधान से लेकर राज्य और केंद्र तक आमजन की आवाज पहुंच रही है तथा लोकतांत्रिक प्रिय है जहां उनकी सहभागिता बढ़ रही है। वेदनाजी ने कहा कि संसदीय मंचों की स्थापना सार्थक रहस और जनसमस्याओं पर चर्चा को पार है, लेकिन वर्तमान में इन मंचों पर सार्थक बहस नहीं हो ला रही है और अधिक समय अवशेषों में व्यतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष, दोनों का दायित्व है कि वे मिलकर जनता की समस्याओं को सदन में उठाए और उसके समाधान की दिशा में कार्य करें।

जयपुर पुलिस का नशे के खिलाफ महाअभियान
518 ठिकानों पर दबिश, एक
दिन में 62 मुकदमे दर्ज

जागरूक जनता नेटवर्क
jagrukjanta.net

जयपुर। राजधानी जयपुर में मादक पदार्थों की अवैध खरीद - फरोख्त के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर छापेमारी की. इस अभियान में साठहत्तर लोगों ने एक दिन में 518 टिकानों पर छापेमारी की. नशे की तस्करी बेचने वालों के खिलाफ 62 नु मादकमे दर्ज किए गए. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशन में जयपुर पुलिस की और से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में चारों जिलों में कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों से संबंधित 62 नु मादकमे दर्ज किए गए. साथ ही पहलू के दर्ज मुकदमों और चालानशुदा मामलों में 51 गिरफ्तारियों की गई तथा जिले में तलाश में 518 टिकानों पर दबिश दी गई.

पूर्व जिले में सबसे ज्यादा टिकानों पर दबिश: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया इस विशेष अभियान के तहत जयपुर पूर्व जिले में 14 प्रकरण दर्ज किए गए और पूर्व में दर्ज प्रकरणों एवं चालानशुदा मामलों में 20 गिरफ्तारियां की गईं. जिले में मादक पदार्थों की तलाश में सर्वाधिक 140 टिकानों पर दबिश दी गई. उन्होंने बताया कि जयपुर पश्चिम जिले में 17 प्रकरण दर्ज कर 7 गिरफ्तारियां की गईं और 135 टिकानों की जांच की गई.

जयपुर दक्षिण में 62 टिकानों पर दबिश: इसी प्रकार जयपुर उत्तर जिले में 14 प्रकरण दर्ज कर 28 गिरफ्तारियां की गईं तथा 121 टिकानों पर दबिश दी गई. जयपुर दक्षिण जिले में 17 प्रकरण दर्ज कर 2 गिरफ्तारियां की गईं और 62 टिकानों की जांच की गई।

**मिशन कर्मयोगी में राजस्थान
देश में दूसरे स्थान पर**

मिश्रण कर्मयोगी के राजस्थाना डेयबोर्ड की समीक्षा के दौरान बनाया गया कि राज्य में 19 लाख 33 हजार से अधिक कार्मिकों ऑन-द-जॉब (ब्रह्मडूथ) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं और प्रमुख राज्यों की केपीआई रैंकिंग में राजस्थाना देश में दूसरे स्थान पर हैं। अब तक 82.25 लाख से अधिक नामांकन के विरुद्ध 49.12 लाख कोर्स पूर्ण किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने नामांकन और कोर्स पूर्ण करने के अंतर को कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार को कम से कम एक घंटा प्रशिक्षण के लिए देने को कहा। साथ ही स्वायत्त स्थान विभागा तथा पंचायती राज विभागा को पोर्टल पर नए कोर्स विकास कोर्स जोड़ने के निर्देश दिए।

**राजकाज पोर्टल, जनअभियोग
निराकरण एवं विधानसभा प्रकरणों
की समीक्षा**

मुख्य सचिव ने राजकाज पोर्टल पर विभागवारारा फाइल मुवमेंट की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर अब तक 54.9 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन हुआ है तथा विभागों ने कम समय में फाइलों का निस्तारण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजकाज वर्जन 2.0 पर वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन एपीएआर मॉड्यूल तथा ईआईआर आधारित स्मार्ट चैट सपोर्ट भी प्रारंभ किया गया है।

मुख्य सचिव ने ई-फाइलों एवं लिवित छक का निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र निस्तारण करने के लिये दृष्टि दिवा। धियानसमा से संबंढित निस्तार प्रश्नो एच पीएलएस प्रकरणी की समीक्षा में बताया गयल क कुल 2 हजार 10 पत्रों में से 98.61 प्रतिशत (1,82,2) हजार भिजवाए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने शेष लेखित प्रकरणी का प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिये दृष्टि दिवा। राखतमान संघर्षक पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गयल क मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 की अवधि में दर्ज 65.92 लाख परिवर्दियों में से 99.56 प्रतिशत (65,63 लाख) का निस्तारण किया गयल है। औसत निस्तारण समय घटकक 12 दिन रह गयल है। तथा परिवर्दियों की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ा है।

सूखा संभावित जिलों में पेयजल एवं चारा प्रबंधन के निर्देश-

मुख्य संचिव ने सूखा संभावित जिलों में आमजन एवं पशुजन को रहत देने के लिए अग्रिम तैयारीयां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला प्रभारी सचिवों को अपने प्रभार वाले सूखा संभावित जिलों का भ्रमण कर धरातलपर आकलन करने तथा जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जन स्वास्थ्य अभियंत्रिका विभाग को पेयजल की सुचारु आपूर्ति के लिए आकरिसिक कार्य-योजना तैयार करने, आवश्यकताानुसार चारा डिपो स्थापित करने तथा गौशालाओं में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जयपुर को मिली नई रेल सौगात, खातीपुरा से सांतरागाछी सुपरफास्ट ट्रेन शुरू

जयपुर @ जागरूक जनता। जयपुर को रेल संपर्क के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन से सांतरागाछी (पश्चिम बंगाल) के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी

दिखाकर रवाना किया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम से वर्रुअली जुड़े। जयपुर के खातापुरा स्टेशन पर आयोजित समारोह में जयपुर सांसद मंजु शर्मा, ग्रेटर नगर निगम महापौर सुनील कोठारी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में यात्री मौजूद रहे।



सुश्री श्रीधरी दीदी



Shreedhardidi.in

NEWS 18
इंडिया

प्रतिदिन (प्रातः)
EVERY DAY
8:30 AM

न्यूज़ 24

प्रतिदिन (प्रातः)
EVERY DAY
6:00 AM

भारत
समाचार

प्रतिदिन (प्रातः)
EVERY DAY
6:50 AM

साधना

प्रतिदिन (प्रातः)
EVERY DAY
8:15 AM

संस्कार

सोम-शुक्र (रात्रि)
MON - SAT
8:30 PM



YouTube JagadguruKripalaujiMaharaj

YouTube Shreedhardidi





JETHI TECH SOLUTIONS

Follow Us: @jethitech







ADDING WINGS TO YOUR BUSINESS

BULK SMS - Lowest Price

Buy 1 Lakh SMS @ Rs.12000/-
 With **FREE** Control Panel
 @ 12 Paisa Per SMS
LIFETIME VALIDITY

START-UP PACKAGE

Dynamic Website
 + Domain & Hosting(1 Year)
 + Social Media Profile Creation
 + Social Media Management* (1 Year)
 + 3 WhatsApp Stickers
 + WhatsApp Chat Direct Link
 + Local Business Listing
 + Logo Design

All For Just
Rs.35,000/- + GST

WEDDING INVITATION

1 Invitation Video for Whatsapp
 10,000 Bulk SMS
 1 Social HashTag Creation
 1 Whatsapp Direct Chat Link
 1 Landing Page

**Send Digital Invitations
 At One Click**

Digital Branding/Marketing

- ★ Youtube Marketing
- ★ Digital Marketing
- ★ Whatsapp Marketing
- ★ Bulk SMS Marketing

- ★ Website Development
- ★ Android Development
- ★ Software Development
- ★ Social Media Management



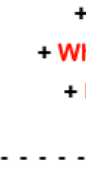
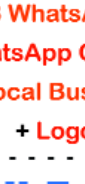

Corporate Branding/Identity

- ★ Visiting Cards
- ★ Pamphlets
- ★ Bill Book
- ★ ID Cards
- ★ Banners
- ★ Brochure
- ★ Letterhead
- ★ Envelope
- ★ Signages
- ★ Calendars
- ★ Diary
- ★ Bags
- ★ Pen Stand
- ★ Paper Weights
- ★ Pen
- ★ Mugs
- ★ T-Shirts
- ★ Many More...

Financial Services: Business Loan, Home Loan, CC Limit, Mortgage Loan

WE ARE 




**DIGITAL MARKETING | CORPORATE BRANDING | PRINT MEDIA
 WEBSITE DESIGN/DEVELOPMENT | SOFTWARE DEVELOPMENT
 ANDROID/iOS APPS | BULK SMS | CRM/ERP SOFTWARE**

INDIA: 1C, Rajputana Marg, Kalyanpuri, Jhotwara, Jaipur-12
USA: 11923 NE Summer St. Portland, Oregon, 97220, USA
 +91-7976625313, +1(503) 8788224 || www.jethitech.com || sales@jethitech.com

सम्पादकीय

रिफाइनिंग महाशक्ति भारत पर गर्व कीजिए

बी ते दिनों जामनगर सुखियों में रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राजदूत सज्जिया गौर की रिलायंस की फ़रान्सीसी वाली इड टाउनशिप की यात्रा राजनीतिक स्तर पर और हमारी घरेलू बहसों के भी केंद्र में रही। अंबानी परिवार द्वारा उनकी मेजबानी चर्चा का विषय बना। अमेरिका भारत की फ़रान्सीसी में इतनी रुचि क्यों ले रहा है? वे अंबानी से वेनेजुएला का तेल खरीदने को क्यों कह रहे हैं? वे भारत को रिफ़ाइनर महशायक क्यों बता रहे और क्षमा बहाने को क्यों कह रहे हैं? संक्षेप में मैं तो रुबियो और गौर जामनगर में क्यों हैं और दिल्ली या बेंगलुरु में क्यों नहीं? आमतौर पर तो विदेशी अतिथि वहीं जाते हैं। संयुक्त प्रगतिशील गणबंधन सरकार का दौरा याद करें। उस समय पश्चिमी देशों के प्रमुखों के इम्फ़ोसिफ़ा या अन्य ठेक कंपनियों के परिसर में जाने पर विवाद नहीं होता था। तब इसे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया जाता था। यहां तक कि वामपंथी दल भी अपनी कारपोरेट विरोधी भावना को किनारे कर देते थे। तो फिर अब इतना संदेह, इतनी शंका और यहां तक कि इतना अविश्वास क्यों दबाने को मिल रहा है? अंबानी परिवार (और भारत) को सबसे दूर वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जबकि रूस कहीं ज्यादा करीब है? जानिए है यह अमेरिकी निरंत्रण वाले वेनेजुएला के तेल को बेचना के लिए दबाव बनाए और पुष्टि पर दबाव बढ़ाने के मकसद से भारत को रूस से दूर करने की एक चाल होनी चाहिए।

रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद में कोई भारी गिरावट नहीं आई है और इसकी संभावना भी कम है। भारत को रिफाइनिंग महंगाई कहना सिर्फ एक बड़ी त्रापी नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के एक शानदार नए पहलू की भी याद दिलाता है। दिवंगत धीरूभाई अंबानी की दूरदर्शिता ने देश को ऊर्जा संसाधनों के अभाव से निकलने का एक रास्ता दिया है। जब किसी विशाल देश के पास हाइड्रोकार्बन संसाधन लगभग न के बराबर हों तो वह क्या करे? वह वैश्विक स्तर पर उस देशों के कच्चे तेल को रिफाइन करना शुरू कर देता है जो अपनी जमीन या समुद्र की तलहटी से तेल निकालते हैं। रिफाइनिंग के बिना कच्चे तेल का कोई उपयोग नहीं है। दुनिया में ऊर्जा की खपत बढ़ रही थी लेकिन रिफाइनिंग क्षमता उस गति से नहीं बढ़ रही थी। भारत ने इस कमी को पूरा किया। अंबानी परिवार की दूरदर्शिता इस बात में भी दिखाई देती है कि उसने वेनेजुएला के भारी समझौते से जुड़ी खास चुनौतियों को पहचाना और उनमें छिपे अवसरों को भी समझा। अगर इस खजाने से भारत रिफाइनिंग के क्षेत्र में एक मछलीकत बना है तो क्या यह उपलब्धि बंगलूर की टेक्नाॅजी और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जितना ही गर्व करने लायक नहीं है? आज दुनिया भर में रिफाइनिंग क्षमता की अमेरिका को जो जरूरत है, खासकर वेनेजुएला के भारी और मीम जैसे घटकों वाले कच्चे तेल के प्रस्सरकरण के लिए, उसके पीछे रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक तीन कारण हैं।

रणनीतिक कारण: अमेरिका ने हाल ही में दबाव बनाकर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करवाया है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। अब अमेरिका को अपनी इस सफलता को व्यावसायिक रूप से भी सफल बनाना है, क्योंकि वह पश्चिमी गोलार्ध को अपने हितों के अनुरूप न सिरे से व्यवस्थित करने में जुटा है।

राजनीतिक कारण: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की अधिक उपलब्धता कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद करती है। ईरान संकट अभी शांत नहीं हुआ है बल्कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद इसके और गंभीर होने की आशंका है।

आर्थिक कारण: वेनेजुएला के तेल से अमेरिकी को व्यावसायिक लाभ या अपना हिस्सा मिलता है। इसके अलावा, जब रिफाइनड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति वैश्विक बाजार में बढ़ती है तो अमेरिका में ईंधन की कीमतें घटने में मदद मिलती है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अगले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी मध्यार्थि चुनावों के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। खासकर तब, जब मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव दूसरा कार्यवाही पूरा कर रहा हो। इस समय रिपब्लिकन पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में वह चाहती है कि महंगाई और पेट्रोल की कीमतें नीचे आएं। इसलिए अमेरिका को अधिक कच्चे तेल और अधिक रिफाइनिंग क्षमता की जरूरत है। अमेरिका आज भी वेनेजुएला के तेल के सबसे बड़े आयातकों में शामिल है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वहां भारी कच्चे तेल की संसाधित करने वाली कई रिफाइनरियां बंद हो गईं। इसकी एक वजह यह रही कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था टेक्नॉलॉजी, वित्त, रॉकेट उद्योग और अब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (आई) जैसे कम संसाधन-निर्भर और अधिक समृद्ध क्षेत्रों की ओर बढ़ गई। टेक्सस, टेक्सास और अमेरिका के पुराने औद्योगिक क्षेत्र पीछे छूटते गए जबकि सिलिकॉन वैली, सिएटल और न्यूयॉर्क जैसे केंद्र आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में भारत के अलावा कौन-सा देश दुनिया के लिए रिफाइनिंग का काम कर सकता है? यूरोप में रिफाइनिंग की क्षमता बहुत कम बची है, जो ग्रेटा थनबर्ग जैसे पर्यावरण कार्यकर्ताओं के प्रभाव के बावजूद कायम रह पाई है। पश्चिम एशिया भी अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाना का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा क्योंकि ईरान और उसके सहयोगी समूहों से खतरा बना हुआ है। भारत को रिफाइनरियों की संख्या और उनकी क्षमता, दोनों बढ़ानी चाहिए।

रोजगार, कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल

युवा शक्ति को अवसर आत्मनिर्भर राजस्थान का संकल्प

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार और परिश्रम को सही दिशा मिल जाए तो विकास की गति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। राजस्थान जैसे विशाल और संभावनाओं से भरपूर प्रदेश के लिए युवाओं का सशक्तीकरण आर्थिक प्रगति और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की युवा-केंद्रित पहलें इसी सोच पर आधारित हैं। रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, उद्यमिता और वित्तीय सहायता तक अवसरों का व्यापक दायरा तैयार करने पर दिया जा रहा जोर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य के 350 से अधिक महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई किरण नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किए गए हैं एवं जिला चिकित्सालयों में राज सवेरा के तहत नशामुक्ति वर्ड स्टोप कार्यक्रम स्थापित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और रोजगार को एक-दूसरे से जोड़कर ही शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी तैयार की जा सकती है।

आतिथ्य सेवाओं, कृषि प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा, खनन, हस्तशिल्प, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ हैं। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है।



इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और उन्हें काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कम हो सकता है। राजस्थान सरकार ने उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौशल नीति- 2025 जारी की है। राज्य सरकार अब तक 3 लाख 70 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी है। यह पिछली सरकार के पांच वर्षों में दिए गए प्रशिक्षण की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है।



इसके अतिरिक्त 144 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। राज्य में 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना और 76 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना भी शिक्षा एवं तकनीकी दक्षता के विस्तार से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहलें छोटे उद्यमों और स्वरोजगार की संभावनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में उपयोगी भूमिका निभाती हैं। प्रदेश में ऋण सुविधाओं के माध्यम से युवाओं को अपने स्वरोजगार के सपनों को पूरा करने में के अवसर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

राजस्थान में युवा कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन सेवाएं, हस्तशिल्प, डिजिटल कनेक्टिविटी, ई-कॉमर्स और स्थानीय जरूरतों से जुड़े कारोबार को व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए केवल ऋण उपलब्ध कराने के साथ युवाओं को व्यवसाय योजना तैयार करने, बाजार की पहचान करने, लागत और आय का आकलन करने, डिजिटल भूगोल अपनाने तथा अपने उत्पादों का प्रचार करने में भी मार्गदर्शन देने की भी व्यवस्था है।

ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध करने एवं विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए बैंकिंग संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में 5 हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत होने तथा 65 आईस्टार्ट लॉन्चपैड स्थापित किए जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण है। इन पहलों का उद्देश्य नए विचारों को व्यावसायिक स्वरूप देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने से जुड़ा है। छोटे शहरों और गांवों के प्रतिभाशाली युवाओं को भी इन सुविधाओं का लाभ दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने युवाओं में नेतृत्व एवं नवाचार जैसे गुणों के विकास के उद्देश्य से नई राजस्थान युवा नीति लागू की है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल के माध्यम से युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की पहल की गई है।

इसी क्रम में माय भारत प्लेटफॉर्म युवाओं को स्वयंसेवा, कौशल विकास और राश निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम बन रहा है। राजस्थान में इस प्लेटफॉर्म पर 26 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है और 1,700 से अधिक संस्थाएं इससे जुड़ी हैं। युवा विकास की चर्चा में खेल और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण हैं। खेल अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व और आत्मविश्वास विकसित करने में। प्रवेश में 17 नए खेलों ईइया केन्द्रस्थ और सभी 41 जिला मुख्यालयों पर एक जिला खेल योजना के अंतर्गत खेल अकादमियों का संचालन किया जा रहा है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोइडयम योजना भी लागू की गई है।

राज्य वे 350 से अधिक महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई किरण नशुमिक केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं जिला चिकित्सालयों में राज सेवरा के तहत नशुमिक वाडी स्थापित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्वरोजगार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और रोजगार को एक-दूसरे से जोड़कर ही शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर युवा पीढ़ी तैयार की जा सकती है। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, निजी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार, उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण, उद्यमों के लिए सूलभूत ऋण और युवाओं को निरंतर मार्गदर्शन आदि सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए घटक हैं। इनके बीच बेहतर समन्वय से रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत तंत्र विकसित हो रहा है। राजस्थान की युवा शक्ति में अपार संभावनाएँ हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की युवा-केन्द्रित नीतियों के सामने समझे महत्वपूर्ण लक्ष्य युवा हैं कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली युवा अवसरों के अभाव में पीछे न रह जाए। जब युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार, ऋण और उद्यमिता का प्रभावी सहयोग मिलेगा, तभी आत्मनिर्भर युवा और समृद्ध राजस्थान का संकल्प साकार हो सकेगा।

ઓપિનિયન

तेजी से बढ़ता एंटीडिप्रेसेंट दवाओं का बाजार

» जागरूक जनता
jagrukjanta.net

हाल ही में देश में मानसिक स्वास्थ्य और एंटीडिप्रेसेंट दवाओं के बाजार को लेकर चर्चाने वाले एकड़े सामने आए हैं। सितंबर, 2026 तक के एक साल में देश का एंटीडिप्रेसेंट बाजार 8.63 फीसदी की बढ़त के साथ 2,842 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। हालाँकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बाजार की कोमल तो बढ़ी है, लेकिन बेची गई दवाओं की कुल संख्या (वॉल्यूम) में 0.76 फीसदी की गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर एंटीडिप्रेसेंट दवाओं का बाजार 2026 में 23.56 बिलियन डॉलर आंका गया है, जिसके 2031 तक बढ़कर 32.25 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। यह तथ्य बताते हैं कि भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति आज भी गंभीर बनी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं की बढ़ती डिमांड का सीधा मतलब यह बिनाकूल नहीं है कि अधिक लोग मानसिक बीमारियों से पूरी तरह ठीक हो रहे हैं।

वहीं दवा बाजार की बात करें तो भारतीय दवाओं का डका दुनिया के दो से अधिक देशों में बज रहा है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 40 फीसदी जेनेरिक दवाएँ और ब्रिटेन (यूके) की कुल दवाओं का 25 फीसदी हिस्सा भारत से ही जाता है। इसके अलावा अफ्रीका की 50 फीसदी से अधिक जेनेरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय दवाओं से होती है। वहीं भारत मात्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। दुनिया भर के कुल टीका उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है। भारत में दवाओं के इस बढ़ते कारोबार के पीछे मुख्य रूप से कई कारण जिम्मा देते हैं। क्रोचिक बीमारियाँ का बढ़ता ग्राफ भी इसे हवा देता का काम



कर रहा है। हाल के महीनों में दिल की बीमारियां एंटी-डायबिटीज, ऑन्कोलॉजी (कैंसर) और सीएनएस (मानसिक स्वास्थ्य) जैसी क्रोनिक थरेपी की दवाओं की मांग में सबसे तेज उछाल देखा गया है।

विशेषज्ञों की मानें तो आज भी कई चुनौतियाँ मानसिक स्वास्थ्य और इलाज को लेकर बनी हुई हैं। मानसिकित्सकों का मानना है कि दवाओं के बढ़ते बाजार के बावजूद मरीजों के पूरी तरह ठीक होने की दर अब भी कम है। इसके पीछे तीन सबसे बड़ी चिंताएँ हैं। पहला खुद से बीमारी का अनुमान लगाना। दूसरा अंग्रेज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने लक्षणों को खुद ही डिप्रेशन या एंजायटी का नाम दे देते हैं। इसका असर ये होता है कि कई बार लोग बिना डॉक्टर की सलाह के पुरानी पंचों या किसी परिवर्तित की दवा देखकर खुद ही एंटीडिप्रेसेंट लेना शुरू कर देते हैं। यह बेहद खतरनाक है, क्योंकि डिप्रेशन की कई स्तर होते हैं और हर मरीज के लिए दवा की खुराक अलग होती है। दूसरी चिंता का कारण है इलाज में अत्यधिक देरी।

समाज में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण लोग अपनी समस्या को लंबे समय तक छुपाते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुँचता है, तब तक बीमारी काफी गंभीर हो चुकी होती है। शुरुआती दौर में जो बीमारी सिर्फ काउंसिलिंग या थेरेपी से ठीक हो सकती थी, उसके लिए फिर लंबे समय तक भारी दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। तीसरी बड़ी चिंता है दवाओं का बीच में ही छोड़ देना।

वहीं एंटीडिप्रेसेंट दवाओं के बाजार मूल्य में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि और चिकी की संख्या में गिरावट के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे दवाओं की बढ़ती कीमतें। बाजार में आई इस तेजी का मुख्य कारण नई, अधिक प्रभावी और कम साइड-इफेक्ट्स वाली दवा आधुनिक दवाओं का आगमन है, जो पुरानी दवाओं की तुलना में काफी महंगी हैं। इसके अलावा सामान्य मुद्रास्फीति ने भी दवाओं के दाम बढ़ाए हैं। दूसरा कारण है शहरी क्षेत्रों में जागरूकता। बड़े शहरों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हिचकिचाहट कम हुई है। लोग अब मनोचिकित्सक के पास जान और दवाएं

मानसिक स्वास्थ्य का बढ़ता बाजार इस बात का प्रमाण है कि लोग अब इस समस्या को लेकर जागरूक हो रहे हैं, लेकिन यह इस बात का संकेत बिल्कुल नहीं है कि समाज स्वस्थ हो रहा है। जब तक समाज से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक नहीं मिटता और लोग समय पर सही चिकित्सा नहीं अपनाएंगे, तब तक दवाओं की बढ़ती विक्री सिर्फ खोखले आर्थिक आंकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगी।

शुरू करने में संकोच नहीं कर रहे हैं, जिससे महंगी दवाओं की मांग बढ़ी है। मानसिक तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण दुनिया भर में इन दवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। इन दवाओं में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटर्स वर्ग की दवाएं सबसे ज्यादा बेची जा रही हैं। इस बाजार में उत्तरी अमेरिका अधिक हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है।

वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में भी डिप्रेशन की दवाओं का बाजार सितंबर, 2026 तक कर के 12 बिलियन डॉलर में करीब 2,842 करोड़ डॉलर तक कर गया है। इसके अलावा दुनियाभर में बढ़ती पुरानी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों के कारण पूरी फार्मा इंडस्ट्री में तेजी से निस्तार हो रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल दवा बाजार में ऑन्कोलॉजी (कैंसर की दवाएं) सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिसका वैश्विक राजस्व अकेले 232.50 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। मोटापा और मधुमेह इस सघन दवा बाजार में सबसे क्रांतिकारी उछाल वजन घटाने और डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं और

